वर्ष-1 , अंक-2 | बेंगलुरु ,गुरूवार ,20 अगस्त 2026 | RNI NO:KNHIN/26/A5540 | Contact:news@bhaarataarth.com | पृष्ठ - 4 ,मूल्य - 5 रुपए

दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

ख़बर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

सीएम विजय के ऐलान पर सदन में गूंजा एमजीआर का गीत

विधायकों को नई कार, 75 हजार भत्ता

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में विधायकों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। सरकार की ओर से सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने के साथ उनके संचालन से जुड़े खर्चों के लिए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक कामकाज के लिए सचिव रखने हेतु भी हर विधायक को अलग से राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं का उद्देश्य विधायकों को अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रियता से काम करने और जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करना है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विधानसभा में टीवीके विधायक सिंधु ने खास अंदाज में उनका आभार जताया। उन्होंने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) का लोकप्रिय गीत कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान गाकर मुख्यमंत्री विजय को धन्यवाद दिया। सदन में विधायक का यह अंदाज चर्चा का विषय बन गया। सरकार के मुताबिक प्रत्येक विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वाहन के ड्राइवर, ईंधन और रखरखाव से जुड़े खर्चों के लिए हर महीने 75 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें जनता से मिलना, विकास कार्यों का निरीक्षण करना और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना होता है। ऐसे में सरकारी वाहन और उससे जुड़ी सुविधाएं मिलने से वे अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। विधायकों के लिए एक अन्य सुविधा की भी घोषणा की गई है। सरकार हर विधायक को 25 हजार रुपये प्रति माह का अनुदान देगी। इस राशि का इस्तेमाल निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े पत्राचार और अन्य आधिकारिक कामकाज में सहायता के लिए एक सचिव नियुक्त करने में किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिकल सहायता मिलने से जनप्रतिनिधि अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बताया कि मौजूदा विधानसभा में कई सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। इनमें कुछ विधायक आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के पास बड़े स्तर पर निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करने और लगातार जनता के बीच रहने के लिए पर्याप्त वित्तीय या लॉजिस्टिकल संसाधन नहीं हो सकते।

मलेशिया से बंबीहा गैंग के तीन वांछित गुर्गे डिपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने विदेश में छिपे अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मलेशिया से देविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांछित आरोपियों को डिपोर्ट कराने में सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग की ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से यह कार्रवाई की। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मलेशिया से डिपोर्ट किए गए तीन आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस बहिबल, अजॉय सिंह और पवनदीप सिंह के रूप में हुई है। तीनों आरोपी पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित थे। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, रंगदारी, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपियों पर लुधियाना में हैंड ग्रेनेड धमाका करने की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। इस मामले के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने की बात सामने आई है। मलेशिया से डिपोर्ट किए जाने के बाद तीनों आरोपियों को नयी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस अब उन्हें पंजाब लाकर आगे की जांच करेगी। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई विदेशों में छिपकर पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ट्रांसनेशनल संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

सार संक्षेप

सेंसेक्स 325 अंक फिसला, गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार

मुंबई । भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 325.78 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,909.68 और निफ्टी 76.60 अंक या 0.32 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,078.30 पर था। बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। सूचकांकों में निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.49 प्रतिशत और निफ्टी एनर्जी 1.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ टॉप लूजर्स थे। निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसई, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी ऑटो, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी फार्मा और निफ्टी कंजप्शन भी लाल निशान में बंद हुए। दूसरी तरफ निफ्टी आईटी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हरे निशान में बंद हुए। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 130.65 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63,408.75 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 101.70 अंक या 0.51 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 19,707.15 पर था।

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो आरोपियों के पैर में लगी गोली

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बुधवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की दो घटनाएं सामने आईं। नंदग्राम थाना क्षेत्र में स्वाट, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम की मोरटी तिराहे पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। नंदग्राम के एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में पहले झपटमारी और लूट की घटनाओं में शामिल कुछ आरोपी दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मोरटी तिराहे पर चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि रुकने के बजाय दोनों संदिग्ध भागने लगे और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

यूपी-बिहार समेत उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। कई राज्यों में लगातार बारिश के बीच मौसम विभाग (आइएमडी) ने अगले कई दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी झारखंड, दक्षिण-पश्चिम बिहार और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बने डिप्रेशन का असर उत्तर और मध्य भारत के मौसम पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 19 अगस्त को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार और झारखंड में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। आइएमडी के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 25 अगस्त के दौरान कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19-20 अगस्त और 23 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 19-20 अगस्त और 24-25 अगस्त को बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जबकि 21 से 23 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में 19 अगस्त के अलावा 22 से 25 अगस्त के दौरान भी कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 20 और 21 अगस्त को भी राज्य में बारिश की संभावना बनी हुई है।

ताज होटल दिल्ली में जुटे जापानी उद्योगपति

सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में निवेश का दिया न्योता

21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य कार्यक्रम

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली के ताज होटल में उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ हाईलेवल सीईओ राउंडटेबल में हिस्सा लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में 200 से अधिक जापानी उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में 3191 करोड़ रुपये की तीन औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आईं। इन परियोजनाओं से 10 हजार से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इनमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाएं शामिल हैं। 500 एकड़ में जापान सिटी कार्यक्रम में यीडा क्षेत्र में करीब 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की योजना भी चर्चा के केंद्र में रही। प्रस्तावित जापान सिटी में जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर और सहायक उद्योगों को भी जगह देने की तैयारी है। इससे एक ही क्षेत्र में उत्पादन से लेकर सप्लाई चेन तक का औद्योगिक नेटवर्क विकसित होने की उम्मीद है।

सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक पर नजर

2025 करोड़ की परियोजना से 3800 रोजगार एस्कॉर्ट्स कुबोटा यीडा के सेक्टर-10 में करीब 2025 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यहां ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और संबंधित उत्पादों के निर्माण की योजना है। इससे करीब 3800 से अधिक रोजगार मिलने की उम्मीद है। मिंडा कॉरपोरेशन सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में करीब 1166 करोड़ रुपये की दो परियोजनाएं लगाएगी। इनसे करीब 6440 रोजगार मिलने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक पर नजर सरकार जापानी निवेश को सिर्फ ऑटोमोबाइल क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहती। बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, क्लीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

तेजस्वी का राजभवन मार्च बना रणक्षेत्र

बैरिकेडिंग तोड़ी गई, वाटर कैनन के बाद नेता प्रतिपक्ष हिरासत में

पटना। बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का राजभवन मार्च पुलिस कार्रवाई के बाद हंगामे में बदल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकले मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। राजभवन मार्च के लिए राजद के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेपी गोलंबर पर एकत्र हुए। मार्च शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नमन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर बढ़े। पुलिस

ने डाकबंगला चौराहे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बैरिकेड लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। इनकम टैक्स चौराहे के पास भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसी दौरान तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं।

झारखंड में छात्रों का आंदोलन खत्म, सरकार को दो महीने का अल्टीमेटम, जांच नहीं हुई तो फिर रांची में जुटेंगे छात्र

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने मंगलवार को आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। इससे एक दिन पहले सोमवार देर शाम देवेंद्रनाथ गुट ने भी अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि, छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन स्थायी रूप से खत्म नहीं हुआ है। राज्य सरकार को जांच पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच की कोर कमेटी की बैठक में आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया। छात्रों के मुताबिक, सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों में जांच और कार्रवाई शुरू की है। ऐसे में सरकार को निष्पक्ष जांच पूरी करने के लिए समय देना जरूरी है। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर दो महीने के भीतर जांच पूरी नहीं हुई या कार्रवाई से छात्र संतुष्ट नहीं हुए, तो वे दोबारा बड़ी संख्या में रांची पहुंचेंगे। उस स्थिति में सीबीआई जांच की मांग आंदोलन का प्रमुख मुद्दा होगी।

छात्र नेताओं का दावा है कि आंदोलन के दबाव में सरकार ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई मामलों पर कदम उठाए हैं।

छात्रों को सीजेपी प्रदर्शनों से दूर रहने का आदेश, विवाद के बाद तमिलनाडु में विजय की पार्टी ने लिया यू-टर्न

चेन्नई: तमिलनाडु में छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों और आंदोलनों से दूर रखने के एक आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विजय थलपति के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) से जुड़े निर्देश में छात्रों और युवाओं को वामपंथी संगठनों तथा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले होने वाले प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने की बात कही गई थी। विरोध बढ़ने के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। बताया गया कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों तथा युवाओं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था। इसमें विशेष तौर पर वामपंथी दलों और सीजेपी से जुड़े आंदोलनों, प्रदर्शनों तथा हड़तालों का उल्लेख किया गया था। आदेश सामने आने के बाद राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच प्रतिक्रिया तेज हो गई। आलोचकों ने इसे छात्रों की अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर सवाल उठाए। आदेश पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई।

जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खां के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनसे जुड़े संस्थानों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार सुबह रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी की टीमों ने कई परिसरों में दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाले तथा कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। ईडी की यह कार्रवाई केवल रामपुर तक सीमित नहीं रही। जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और दिल्ली में भी कई स्थानों पर तलाशी ली। बताया जा रहा है कि कुल करीब 10 परिसरों में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत कार्रवाई की गई है। ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के मुताबिक, जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निजी ठेकेदारों के जरिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त धन का कथित तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया गया। जांच में ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े निर्माण कार्यों तथा कुछ ठेकेदारों के बीच हुए वित्तीय लेनदेन को भी शामिल किया गया है। एजेंसी कथित तौर पर सरकारी अनुबंधों से जुड़े धन के संभावित डायवर्जन, दान और अन्य आर्थिक लाभों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सहारनपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के कार्यालय और आवास पर ईडी की टीम पहुंची। वहीं दिल्ली में जौहर एसोसिएट्स से जुड़े सैयद खालिद के आवास पर भी तलाशी ली गई। जांच एजेंसी इन परिसरों से वित्तीय दस्तावेजों, लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है। ईडी की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने संबंधित परिसरों में मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी जांच की। एजेंसी का फोकस कथित तौर पर सरकारी धन के इस्तेमाल और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने पर है। जांच के दायरे में रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी, ए एंड एस इंटरप्राइजेज, सीके एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, सीके एसोसिएट्स के निदेशक पवन कुमार जैन और शाहीन खान के आवास शामिल बताए गए हैं। सहारनपुर में दीपक गुप्ता के कार्यालय और आवास तथा दिल्ली में जौहर एसोसिएट्स के पार्टनर सैयद खालिद के आवास पर भी तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। मौजूदा छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण जांच की अगली दिशा तय करने में अहम हो सकता है। आजम खां फिलहाल कई मामलों में सजा के बाद जेल में हैं। ताजा कार्रवाई के बाद उनके समर्थकों और करीबियों के बीच भी हलचल बढ़ गई है। हालांकि, ईडी की जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही आरोपों और वित्तीय लेनदेन की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

झारखंड में बार-बार पेपर लीक की हो निष्पक्ष जांच, सुनी जाए छात्रों की समस्या: दिलीप घोष

कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और राज्य में कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बार-बार प्रश्न-पत्र लीक होने की घटनाओं पर सवाल उठाना पूरी तरह जायज है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और प्रश्न-पत्र लीक के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि आखिर बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है और उसकी पहचान कर जांच की जानी चाहिए, जिससे छात्रों की शिकायतों और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं, मस्जिदों समेत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर घोष ने कहा कि कई जगहों पर बिना अदालत या पुलिस की अनुमति के माइक्रोफोन लगाए गए थे। कई स्थानों पर ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था। नियमों का पालन कराने के दौरान हजारों स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आरोपों से जुड़ी पीआईएल खारिज किए जाने पर भी घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोर्ट या पुलिस की अनुमति से लाउडस्पीकर नहीं लगाए गए थे। उन्हें गैर-कानूनी तरीके से लगाया गया था और आवाज का स्तर भी तय सीमा से ज्यादा था। इसीलिए हजारों जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए। लोगों ने खुद ही उन्हें हटा दिया, और जहां उन्होंने ऐसा नहीं किया, वहां पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं है। दूसरे धर्मों के भी कई पूजा-स्थल हैं जहां लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता था और सभी ने नियमों का पालन किया है। जिन्होंने पालन नहीं किया, वे कोर्ट गए और कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से उनकी याचिका खारिज कर दी।

संपादकीय

सरकार की सही पहल

नरेन्द्र मोदी जिस काम को नहीं कर सके, वो काम राहुल गांधी ने कर दिखाया। झारखंड में छात्र आंदोलन में राहुल गांधी के सार्थक हस्तक्षेप ने सकारात्मक राजनीति का रास्ता तैयार किया है। गौरतलब है कि झारखंड में 24 दिनों लंबा छात्र आंदोलन चला। आंदोलनकारियों की मांग थी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। छात्रों ने पेपर लीक के साथ-साथ ओएमआर शीट में धांधली, अयोग्य एजेंसियों को परीक्षा का ठेका देना और कट-ऑफ जारी न करने के आरोप भी लगाए। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो समेत कुछ आंदोलनकारियों ने अनशन भी किया था। जंतर-मंतर पर हुए सफल आंदोलन के ठीक बाद झारखंड में आंदोलन खड़ा हुआ तो जाहिर तौर पर देश की निगाहें वहां गईं। देखते ही देखते आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। झारखंड में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, तो दिल्ली में मात खाई भाजपा को एक बड़ा अवसर मिल गया कि वह रांची में हिसाब-किताब बराबर कर ले। लेकिन राहुल गांधी की सूझबूझ और दूरदृष्टि ने भाजपा के इस खेल को भी खराब कर दिया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रदर्शनकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सुझाव देते हुए एक पत्र लिखा। इसमें राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन कर बातचीत शुरू करना सराहनीय है, लेकिन फिर भी कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में सरकार को छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए। राहुल गांधी ने 14 अगस्त को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की कि वे प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें ताकि उनकी बची हुई समस्याओं का समाधान हो सके। राहुल ने कहा था कि संविधान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। झारखंड के युवाओं का यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उनकी मांगें जायज हैं। यह पत्र 17 तारीख को सार्वजनिक चर्चा में आया और उसी रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्रा.लि. (टीडीपीएल) के माध्यम से हुई सभी भर्तियां और उनके परिणाम भी निरस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि 2014 से टीडीपीएल के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराई जाएगी, जबकि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति बनाई जाएगी। इस फैसले के बाद देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हेमंत सोरेन ने माना कि सरकार के पास परीक्षा कराने के लिए पहले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी मौजूद था, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हमारे पास एसओपी पहले से था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसी वजह से हाल के वर्षों में परीक्षाओं में गड़बड़ियां आईं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को पूरी पारदर्शिता के साथ सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने छात्रों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को जांच कर रही विशेषज्ञ समिति के साथ साझा किया जाएगा ताकि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जा सकें। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों के हित में उनकी सरकार पहले ही पेपर लीक रोकने के लिए कानून बना चुकी है। उन्होंने कहा कि अब परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए और भी सुधार किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की शिकायतें दोबारा सामने न आएं। किसी भी सरकार के मुखिया को व्यवस्था में सुधार की जो बातें कहना चाहिए, वही सब हेमंत सोरेन ने कही हैं। हालांकि परीक्षा माफिया देश की व्यवस्था में इतने गहरे तक जड़ें जमा चुका है कि उसे एकदम से खत्म करना आसान नहीं होगा। इस भ्रष्टाचार में करोड़ों-अरबों का हेर-फेर होता है, और एक साथ कई लोग इसमें संलिप्त रहते हैं। इसलिए इससे वही सरकार सख्ती से निपट सकती है जो बिल्कुल दबाव में न आए और अपने सख्त फैसलों पर कायम रहे। निकट भविष्य में हेमंत सोरेन इस कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, यह देखना होगा। लेकिन अभी कम से कम उन्होंने राहुल गांधी की बात सुनकर सही फैसला लिया है। आंदोलनकारी छात्र सरकार से लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। इस आग में घी डालने का काम भाजपा उसके सहयोगी संगठन और साथी मीडिया अच्छे से कर रहा था। आंदोलन के शुरू से राहुल गांधी का नाम लेकर पूछा जा रहा था कि वे रांची क्यों नहीं आते और क्यों आंदोलनकारियों का साथ नहीं देते। हालांकि राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों से फोन पर बात की थी और जब झारखंड पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया तो उसकी निंदा भी की थी।

चीन का आइस सिल्क रोड, आर्कटिक में सबसे पहले पहुंचना क्यों मायने रखता है

> इतिहास में हर बड़े व्यापारिक मार्ग ने उसी को पुरस्कृत किया है जिसने उसे सबसे पहले मानचित्रित, सुरक्षित और सामान्य किया, मसालों के मार्गों पर वेनिस, स्वेज पर ब्रिटेन, और युद्धोत्तर प्रशांत महासागर पर अमेरिका। अब चीन आर्कटिक में वही भूमिका चाहता है, और इसे हासिल करने के लिए उसने असाधारण तेजी दिखाई है। इसका ट्रिगर मध्य पूर्व रहा है। हूती हमलों से बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में बाधा और ईरान युद्ध से होर्मुज जलडमरूमध्य पर दबाव के चलते, 23 जुलाई 2026 को टैंकरों पर हमलों के बाद तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं, और शिपिंग कंपनियां रेड सी कॉरिडोर को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गईं। चीन का जवाब था उस मार्ग को तेजी से आगे बढ़ाना जिसे वह वर्षों से चुपचाप तैयार कर रहा थारू रूस के नॉर्दर्न सी रूट (एनएसआर) के माध्यम से आइस सिल्क रोड, जो एशिया और यूरोप के बीच गर्मियों के पारगमन समय को लगभग आधा कर सकता है।

असद मिर्जा

पिघलती बर्फ और सुलगते मध्य पूर्व ने चीन को एक नया व्यापारिक मार्ग और एक शुरूआती बढ़त दे दी है। जैसे-जैसे बीजिंग नॉर्दर्न सी रूट को एक कार्यशील शिपिंग कारोबार में बदल रहा है, वह चुपचाप इस नक्शे को फिर से खींच रहा है कि वैश्विक व्यापार पर किसका नियंत्रण है और भारत सहित अन्य देश इससे तालमेल बिठाने के लिए जूझ रहे हैं। इतिहास में हर बड़े व्यापारिक मार्ग ने उसी को पुरस्कृत किया है जिसने उसे सबसे पहले मानचित्रित, सुरक्षित और सामान्य किया, मसालों के मार्गों पर वेनिस, स्वेज पर ब्रिटेन, और युद्धोत्तर प्रशांत महासागर पर अमेरिका। अब चीन आर्कटिक में वही भूमिका चाहता है, और इसे हासिल करने के लिए उसने असाधारण तेजी दिखाई है। इसका ट्रिगर मध्य पूर्व रहा है। हूती हमलों से बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में बाधा और ईरान युद्ध से होर्मुज जलडमरूमध्य पर दबाव के चलते, 23 जुलाई 2026 को टैंकरों पर हमलों के बाद तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं, और शिपिंग कंपनियां रेड सी कॉरिडोर को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गईं। चीन का जवाब था उस मार्ग को तेजी से आगे बढ़ाना जिसे वह वर्षों से चुपचाप तैयार कर रहा थारू रूस के नॉर्दर्न सी रूट (एनएसआर) के माध्यम से आइस सिल्क रोड, जो एशिया और यूरोप के बीच गर्मियों के पारगमन समय को लगभग आधा कर सकता है। नतीजे अब प्रयोगात्मक नहीं रह गए हैं। सितंबर 2025 में, कंटेनर जहाज इस्तांबुल ब्रिज ने चीन-यूरोप के बीच पहली सीधी आर्कटिक यात्रा पूरी की, जो निंगबो-झोऊशान से फेलिक्सटो, हैम्बर्ग और गदान्स्क होते हुए नीदरलैंड्स पहुंचा, इस यात्रा को चीन के परिवहन मंत्रालय ने दुनिया का पहला आर्कटिक कंटेनर मार्ग बताया, जो विशेष रूप से श्सीमा-पार ई-कॉमर्स और उच्च मूल्य-वर्धित वस्तुओं के

लिए डिजाइन किया गयाश था। अगस्त 2026 तक, चीनी शिपिंग कंपनी सी लीजेंड ने उस पहली यात्रा को एक नियमित साप्ताहिक सेवा में बदल दिया था, और चाइना शिप ओनर्स एसोसिएशन ने जुलाई-सितंबर की एक औपचारिक आर्कटिक शिपिंग विंडो और 20,000 टीईयू की संयुक्त कंटेनर व बहुउद्देशीय बेड़े क्षमता की पुष्टि की। जो काम एक अकेले जहाज द्वारा अनजाने पानी को टटोलने से शुरू हुआ था, वह एक साल के भीतर व्यापारिक ढांचे का एक नियमित हिस्सा बन गया है। चीन की जल्दबाजी सोची-समझी है, और यह उन तीन गणनाओं पर टिकी है जिन्हें चीनी सरकारी मीडिया ने स्पष्ट रूप से बताया है। पहला है अतिरिक्त सुरक्षारू बीजिंग नहीं चाहता कि यूरोप के साथ उसका व्यापार किसी एक ही कॉरिडोर का बंधक बने। दूसरा है रूस के साथ रिश्ता। चूंकि एनएसआर लगभग पूरी तरह रूस-नियंत्रित जलक्षेत्र से होकर गुजरता है। चीन की शिपिंग कंपनियां रूस के मौन सहयोग से इस मार्ग पर काम करती हैं, जिससे चीनी शिपिंग को एक ऐसी संरचनात्मक बढ़त मिलती है जिसकी बराबरी फिलहाल एमएससी, मार्स्क और अन्य बड़ी पश्चिमी कंपनियां नहीं कर पातीं। तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण, है मानक तय करना। शिपिंग मार्ग केवल भौगोलिक नहीं होते, वे बीमा ढांचों, बंदरगाह प्रोटोकॉल, आइसब्रेकर-एस्कॉर्ट व्यवस्थाओं और शेड्यूलिंग मानदंडों से बनते हैं, जो एक बार स्थापित हो जाने के बाद नए प्रवेशकताओं के लिए दोहराना महंगा साबित होता है। बीजिंग की आर्कटिक मुहिम को उस व्यापक पैटर्न से अलग करके नहीं देखा जा सकता जो ईरान युद्ध के बढ़ने के बाद से दिखाई दे रहा है, चीनी व्यापार और ऊर्जा को ढोने वाली हर धमनी को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित करना। चीन ने एक साथ मध्य एशिया के मिडिल कॉरिडोर के जरिए जमीनी मार्गों को गहरा किया है, कजाखस्तान के साथ सड़क मार्गों का विस्तार किया है जो अब उसके मध्य एशियाई व्यापार का आधे से अधिक हिस्सा सड़क मार्ग से ढोते हैं, और आर्कटिक विकल्प को आगे बढ़ाया है, एक ही अंतर्निहित आशंका के विरुद्ध तीन अलग-अलग बीमा पॉलिसियां, कि पश्चिम-प्रभुत्व वाले समुद्री अड़चन बिंदुओं का इस्तेमाल कभी चीनी व्यापार के खिलाफ किया जा सकता है। चीनी सरकारी मीडिया आर्कटिक को संप्रभुता और सुरक्षा के आधार पर भी दृढ़ता से पेश करता है, इस क्षेत्र में चीन खतरा के पश्चिमी दावों को खारिज करते हुए और इस बात पर जोर देते हुए कि बीजिंग की गतिविधियां, एक स्वघोषित निकट-आर्कटिक राज्य के रूप में, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत वैध और किसी सैन्य इरादे से मुक्त हैं। पश्चिमी शिपिंग कंपनियों और यूरोप के लिए, आइस सिल्क रोड केवल एक भू-राजनीतिक समस्या नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धी समस्या भी है। अगर चीनी झंडे वाले जहाज निंगबो से फेलिक्सटो तक की यात्रा स्वेज के रास्ते 40 दिनों के मुकाबले लगभग 18-20 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो यूरोपीय आयातकों को एक तेज, सस्ता विकल्प मिलता है, लेकिन ऐसा विकल्प जो चीन-रूस शिपिंग अवसंरचना, बीमा और बंदरगाह संचालन पर तेजी से निर्भर होता जा रहा है, जिससे उस निर्भरता में और गहराई आती है जिसे ब्रसेल्स वर्षों से कम करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी देशों और मिस्र के लिए, एक टिकाऊ आर्कटिक विकल्प उस दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ को कमजोर करता है जो स्वेज और होर्मुज ने पैदा किया है, भले ही, जैसा कि कुछ विश्लेषक आगाह करते हैं, आर्कटिक कंटेनर यातायात आने वाले वर्षों तक एक पूर्ण विकल्प के बजाय एक मौसमी अतिरिक्त साधन ही बना रहेगा, शिपिंग विंडो अभी भी केवल जुलाई के अंत से सितंबर के अंत तक ही चलती है। भारत के लिए, दांव अधिक जटिल हैं। नई दिल्ली आर्कटिक के खुलने में महज एक दर्शक नहीं है ,उसका अपना मार्ग भी विकासाधीन है, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो 2024 से चालू है, और जो भारतीय बंदरगाहों तथा रूस के सुदूर पूर्व के बीच पारगमन समय को 40 से अधिक दिनों से घटाकर लगभग 24 दिन कर चुका है। भारत ने इस कॉरिडोर को एनएसआर से खुद जोड़ने के लिए रूस के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, रूसी संस्थानों के माध्यम से भारतीय नाविकों को ध्रुवीय नौवहन का प्रशिक्षण दिलाया है, स्वदेशी रूप से चार आइसब्रेकर-सक्षम जहाजों के निर्माण का आदेश दिया है, और आर्कटिक काउंसिल में पर्यवेक्षक की भूमिका पाने की महत्वाकांक्षा जताई है। रूसी अधिकारियों ने खुलेआम एनएसआर से जुड़ी अवसंरचना में भारतीय निवेश को आमंत्रित किया है, विश्लेषकों के अनुसार, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मॉस्को नहीं चाहता कि उसका उत्तरी कॉरिडोर पूरी तरह चीनी पूंजी और यातायात पर निर्भर हो जाए।

भारी वर्षा और धराशायी होती हरियाली

> वर्षा की रिमझिम फुहारें उमस से राहत देती हैं, खेतों में नई आशा जगाती हैं और और धरती को हरीतिमा की मनोहारी चादर पहना देती हैं। किंतु यही वर्षा जब अतिवृष्टि में बदल जाती है, तो जलभराव, बाढ़, भूस्खलन और वृक्षों के धराशायी होने जैसी घटनाएं जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति विशेष रूप से सामने आई हैकृमहानगरों और नगरों में भारी वर्षा तथा तेज हवाओं के साथ बड़ी संख्या में वृक्षों का गिरना। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरों में मानसून के दौरान सड़कों पर गिरे बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, गुलमोहर और यूकेलिप्टस के वृक्ष अब सामान्य दृश्य बन गए हैं। फुटपाथों और सड़क किनारे खड़े ये विशाल वृक्ष कभी छाया, स्वच्छ वायु और जैव विविधता के प्रतीक थेय आज वही यातायात अवरोध, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कभी-कभी जान-माल की हानि का कारण बन रहे हैं। यह समस्या केवल नगरों तक सीमित नहीं है। राजमार्गों पर भी वर्षों पुराने आम, इमली और जामुन के वृक्ष तेज वर्षा में गिरकर यातायात रोक देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वन क्षेत्रों के वृक्ष अपेक्षाकृत कम गिरते हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या वर्षा नहीं, बल्कि शहरी परिस्थितियां हैं। वृक्षों का असमय गिरना केवल बादलों या तेज हवाओं का दोष नहीं है। इसके पीछे पारिस्थितिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की विफलताएं छिपी हैं। शहरों में वृक्षों की जड़ों के चारों ओर सीमेंट और कांक्रीट बिछा दी जाती है, जिससे उन्हें फैलने और पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता।

अरुण कुमार डनायक

भारतीय मानसून केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं हैय यह जीवन और विनाश, दोनों का एक साथ आगमन है। वर्षा की रिमझिम फुहारें उमस से राहत देती हैं, खेतों में नई आशा जगाती हैं और और धरती को हरीतिमा की मनोहारी चादर पहना देती हैं। किंतु यही वर्षा जब अतिवृष्टि में बदल जाती है, तो जलभराव, बाढ़, भूस्खलन और वृक्षों के धराशायी होने जैसी घटनाएं जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति विशेष रूप से सामने आई हैकृमहानगरों और नगरों में भारी वर्षा तथा तेज हवाओं के साथ बड़ी संख्या में वृक्षों का गिरना। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरों में मानसून के दौरान सड़कों पर गिरे बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, गुलमोहर और यूकेलिप्टस के वृक्ष अब सामान्य दृश्य बन गए हैं। फुटपाथों और सड़क किनारे खड़े ये विशाल वृक्ष कभी छाया, स्वच्छ वायु और जैव विविधता के प्रतीक थेय आज वही यातायात अवरोध, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कभी-कभी जान-माल की हानि का कारण बन रहे हैं। यह समस्या केवल नगरों तक सीमित नहीं है। राजमार्गों पर भी वर्षों पुराने आम, इमली और जामुन के वृक्ष तेज वर्षा में गिरकर यातायात रोक देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वन क्षेत्रों के वृक्ष अपेक्षाकृत कम गिरते हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या वर्षा नहीं, बल्कि शहरी परिस्थितियां हैं। वृक्षों का असमय गिरना केवल बादलों या तेज हवाओं का दोष नहीं है। इसके पीछे पारिस्थितिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की विफलताएं छिपी हैं। शहरों में वृक्षों की जड़ों के चारों ओर सीमेंट और कांक्रीट बिछा दी जाती है, जिससे उन्हें फैलने और पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। वर्षा का जल भी भूमि में समाने के बजाय नालियों में बह जाता है, परिणामस्वरूप जड़ों का प्राकृतिक पोषण बाधित हो जाता है। बहुमंजिला इमारतों, बेसमेंट, सीवेज लाइन, जल पाइपलाइन और भूमिगत केबलों के निर्माण के दौरान की जाने वाली अनियोजित खुदाई तथा ड्रिलिंग से जड़ें कट जाती हैं और वृक्ष भीतर ही भीतर कमजोर हो जाते हैं। अनेक पुराने वृक्ष दीमक और फफूंद के संक्रमण से खोखले भी हो चुके होते हैं। ऐसे वृक्ष जब तेज हवा और मूसलाधार वर्षा का संयुक्त दबाव झेलते हैं, तो उनका गिरना लगभग निश्चित हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण अवैज्ञानिक छंटाई है। अनेक नगरों में वृक्षों की नियमित वैज्ञानिक छंटाई नहीं होती, जबकि कहीं-कहीं अत्यधिक छंटाई कर दी जाती है। कई बार मुख्य तना काट दिए जाने से वृक्ष सीधे ऊपर बढ़ने के बजाय एक ओर फैलने लगते हैं। ऊपर का भार बढ़ता जाता है, जबकि कांक्रीट में जकड़ी जड़ें उसे संभालने में असमर्थ रहती हैं। परिणामतरू तेज हवाओं में वृक्ष संतुलन खो बैठते हैं। वृक्ष गिरने के बाद नगर निगमों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सीमित जनशक्ति और पुराने उपकरणों के कारण कई स्थानों पर आज भी कुल्हाड़ी और आरी से वृक्ष काटकर हटाए जाते हैं। परिणामस्वरूप सड़कें कई घंटों या कई दिनों तक बाधित रहती हैं। आधुनिक हाइड्रोलिक ट्री-कटर, क्रेन और मोबाइल वुड-चिपर जैसी मशीनों का उपयोग अभी भी अधिकांश भारतीय नगर निकायों में सामान्य नहीं हो पाया है। समस्या का एक कानूनी पक्ष भी है। दिल्ली सरकार ने जून 2025 में एक अधिसूचना जारी कर मृत, रोगग्रस्त अथवा जन-सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके वृक्षों को हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पूर्व अनुमति के बिना वृक्षों की कटाई, छंटाई अथवा प्रत्यारोपण की सीमित छूट का भी प्रावधान किया गया था। किंतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों के नाम पर वृक्षों को काटने या उनकी छंटाई के लिए सामान्य छूट नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल वास्तविक और प्रमाणित खतरे की स्थिति में ही ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए तथा प्रत्येक मामले में पर्यावरणीय संतुलन और जनहित का समुचित परीक्षण आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह रुख उचित है, किंतु इसके साथ ही जोखिमग्रस्त वृक्षों की पहचान और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए त्वरित एवं पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है।

1400 साल से फहराती ध्वजा, माणिक्य स्वामी जिनालय में होगा भव्य ध्वजारोहण

भारतार्थ खबर। संवाददाताः धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

बैंगलोर, 19 अगस्त 2026। श्री जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, बसवनगुडी के तत्वावधान में चातुमार्सार्थ विराजित प. पूज्य साध्वी श्री प्रियश्रद्धांजना श्री जी म. सा. ने प्रवचन में कर्म, ध्यान और आत्मशुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जानबूझकर और ज्ञानपूर्वक की गई गलती को आभोग दुर्ध्यान, जबकि अज्ञान एवं अनजाने में हुई गलती को अनाभोग दुर्ध्यान कहा जाता है।

साध्वीश्री ने कहा कि चक्रवर्ती यदि जीवन के अंतिम समय में संयम धारण करते हैं तो उन्हें शुभगति प्राप्त होती है। वहीं, संयम ग्रहण किए बिना पर्याय पूर्ण करने पर आत्मा को नरक गति प्राप्त होने का विधान बताया गया है। उन्होंने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि रौद्र ध्यान के परिणामस्वरूप उन्हें सातवीं नरक गति प्राप्त हुई।

1400वीं ध्वजारोहण के लिए संघ ने दिया निमंत्रण

प्रवचन के दौरान हैदराबाद एवं कुलपाक तीर्थ से आए संघ के पदाधिकारी परमात्मा माणिक्य स्वामी जिनालय के 1400वें ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण लेकर पहुंचे। संघ के सुरेंद्र बांठिया, वसंत बाफना, इंदर चंद जैन, सुरेश लामाणी, गौतम चंद जैन सहित पदाधिकारियों ने सकल संघ, गुरुदेव एवं गुरुवर्या श्री जी को समारोह में पधारने की विनती की।

बताया गया कि माणिक्य स्वामी जिनालय की ध्वजा लगातार 1400 वर्षों से फहराई जा रही है। आयोजकों के अनुसार, यह परंपरा विश्व के प्राचीनतम जैन जिनालयों की गौरवशाली धार्मिक परंपराओं में विशेष स्थान रखती है।

यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिन मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराजा की निश्रा में आयोजित किया जाएगा।

पोस्टर का हुआ विमोचन

ध्वजारोहण समारोह के पोस्टर का विमोचन ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजराज मालानी, उपाध्यक्ष बाबूलाल भंसाली, महामंत्री कुशलराज गुलेच्छा, तेजराज गुलेच्छा, कोषाध्यक्ष रंजीत ललवानी सहित उम्मेदराज बाफना, पुखराज कवाड़, ललित डाकलिया एवं अन्य सदस्यों ने किया।

3600 से अधिक आराधक कर रहे तपस्या

धार्मिक आयोजन को लेकर जैन समाज में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों के अनुसार, बैंगलोर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में माणिक्य स्वामी तप के 3600 से अधिक आराधक तपस्या में संलग्न हैं। तपस्या एवं धार्मिक आराधना के माध्यम से श्रद्धालु आत्मकल्याण और आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।

1400वीं ध्वजारोहण की ऐतिहासिक परंपरा और व्यापक तप आराधना के चलते इस आयोजन को लेकर जैन समाज में विशेष उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है।

एक खत्म, दूसरा शुरू

झारखंड में करीब 25 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विवादित कंपनी टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी-14, जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही घोषणा कर दी कि जेपीएससी 11 व 13 की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं के घोषित परिणाम भी रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। यानी टीडीपीएल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी चुने गए, उनका चयन भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ग्यारह मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श किया। छात्र आंदोलन के दबाव में काम कर रही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली। दरअसल, छात्रों के कई खेमे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया,उनमें चौदहवीं जेपीएससी सिविल सेवा रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और सिविल जूनियर आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। दरअसल, इन परीक्षाओं का संचालन जेपीएससी के माध्यम से किया गया। वहीं दूसरी ओर सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरियां भी अब समाप्त मानी जाएंगी। सरकार ने वायदा किया है कि वर्ष 2014 के बाद हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच भी की जाएगी। यह जांच कार्य एक न्यायिक आयोग करेगा। बाकायदा एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में सुधारों के लिये एक कमेटी भी बनायी गई है। हालांकि, कुछ आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि, सरकार की घोषणा के बाद छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन इस घोषणा के बाद सचिवालय परिसर में उन नियुक्त प्रतिभागियों की भीड़ जुट गई, जो जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा उतीर्ण करके नौकरी हासिल कर चुके थे। सरकार की घोषणा के तुरंत बाद विभिन्न चयनित प्रतिभागियों का हुजूम सचिवालय में जमा होना शुरू हुआ। उनके लिये यह खबर स्तब्ध करने वाली थी। उनका दुख और गुस्सा स्वाभाविक ही है। बहरहाल, अब राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद हटाये गए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री एक बयान देकर दो हजार लोगों को सरकारी नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? वे इसे सरकारी अन्याय बता रहे हैं। उनकी दलील है कि हम सुबह नौकरी पर थे,लेकिन शाम होते ही हमें नौकरी से हटा दिया गया। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमें नौकरी मिली है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा सितंबर 2024 में फिर से हुई। फिर पेपर लीक की आशंका के बीच मामला अदालत पहुंचा।

JSSC-CGL रद्द होने पर बवाल, नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थी सड़क पर

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

रांची, 19 अगस्त 2026। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं के परिणाम रद्द किए जाने के फैसले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। JSSC-CGL समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए नौकरी बहाल करने की मांग की और न्याय नहीं मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा में सफलता मिली और कई उम्मीदवारों ने नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरियां तक छोड़ दी थीं। अब परिणाम रद्द होने से उनके सामने रोजगार और भविष्य का संकट खड़ा हो गया है।

दोषियों पर कार्रवाई हो, सही अभ्यर्थियों को सजा क्यों?

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया में कहीं अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका तर्क है कि सभी चयनित उम्मीदवारों को एक

ही तराजू में तौलना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है।

एक अभ्यर्थी ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि जिस कार्यालय में वह कुछ दिन पहले तक काम कर रहा था, अब उसी कार्यालय में प्रवेश से रोक दिया गया है। अभ्यर्थियों ने सरकार से पूरे मामले की अलग-अलग जांच कर निर्दोष चयनित उम्मीदवारों को राहत देने की मांग की।

CBI जांच की मांग

BJP सांसद दीपक प्रकाश ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी मामले की सच्चाई सामने लाने और कथित बड़े दोषियों तक पहुंचने के लिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए सत्ताधारी दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की संभावित भूमिका की जांच की मांग की। दीपक प्रकाश ने दावा किया कि आंदोलन कर रहे छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

44 भर्ती परीक्षाओं पर असर

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वर्ष 2014 से JPSC और आउटसोर्स एजेंसी ळरफडेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) के माध्यम से आयोजित की गई 44 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम रद्द किए गए हैं।

इनमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।

आंदोलन का 26वां दिन

छात्र नेता रवींद्र पासवान के अनुसार, उनका आंदोलन बुधवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गया। सरकार के नोटिफिकेशन में कअर अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का उल्लेख है। यह समिति खढरउ और खसरउ में परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अध्ययन कर दो महीने में रिपोर्ट सौंपेगी।

हालांकि, छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से जिस न्यायिक जांच की बात कही गई थी, उसका स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति तय करने के लिए कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इसके बाद आंदोलन की अगली दिशा घोषित की जाएगी।

नौकरी बहाली पर अड़े अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने मेहनत और निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की है, उन्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। अब सरकार के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन किस दिशा में जाता है और क्या मामला अदालत तक पहुंचता है, इस पर सबकी नजर है।

महुआ मोइत्रा पर गिरफ्तारी वारंट, 28 अगस्त को पेश होगी रिपोर्ट

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

कोलकाता, 19 अगस्त 2026। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (ळटउ) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। यह कार्रवाई कथित हेट स्पीच मामले में अदालत के बार-बार जारी समन के बावजूद पेश न होने पर की गई है। कृष्णानगर की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर अमल की रिपोर्ट 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद सांसद महुआ मोइत्रा की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी को कई बार अदालत में पेश होने के लिए समन भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद वह निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हुईं।

अदालत के अनुसार, मंगलवार को भी मोइत्रा को अगले दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वह बुधवार को भी अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद कृष्णानगर अदालत के तीसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट

ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार अदालत के निदेर्शों की अनदेखी आरोपी के आदेशों के अनुपालन के प्रति लापरवाह रवैये को दशार्ती है। ऐसी स्थिति में अदालत के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत में आशंका जताई कि यदि सांसद अदालत में पेश होना अपने आप में दोष सिद्ध होने का अथ नहीं है। मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना बाकी है।

होती हैं तो अदालत परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है। किन आरोपों में दर्ज है मामला?

पुलिस के अनुसार, महुआ मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं की गरिमा का अपमान करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और कथित हेट स्पीच से जुड़े आरोपों में शिकायत दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय न्याय संहिता (इठर) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। 28 अगस्त को सामने आएगी अगली तस्वीर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर अमल की रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस तारीख पर टिकी हैं कि पुलिस वारंट पर क्या कार्रवाई करती है और मामले में अदालत के सामने आगे क्या स्थिति रखी जाती है। फिलहाल गिरफ्तारी वारंट जारी

यूपी में BJP का बड़ा टिकट प्लान! 200 विधायकों पर संकट

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

लखनऊ, 19 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति के तहत पार्टी मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन और जमीनी पकड़ की व्यापक समीक्षा कर रही है। इसी बीच करीब 200 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चा ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी किसी अंतिम सूची की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

विनोद तावड़े तैयार कर रहे रिपोर्ट कार्ड

उत्तर प्रदेश इखढ के प्रभारी बनाए गए विनोद तावड़े को पार्टी के मौजूदा विधायकों की जमीनी स्थिति और प्रदर्शन का आकलन करने की जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि तावड़े पिछले कई महीनों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में संगठन और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में जुटे हैं। पार्टी के आंतरिक आकलन में विधायकों के कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता, जनता के बीच उनकी छवि और संगठन के साथ तालमेल जैसे पहलुओं को देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों के प्रति स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी सामने आई है।

200 सीटों पर बदलाव की चर्चा

BJP के संभावित टिकट बदलाव के पीछे एंटी-इनकंबेंसी को बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में कुछ विधायकों को लेकर जनता की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कई क्षेत्रों में मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट होने के बावजूद स्थानीय विधायक की सक्रियता से खुश नहीं हैं। ऐसे में पार्टी शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय स्तर की नाराजगी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर चेहरे बदलने पर विचार कर सकता है। हालांकि, करीब 200 विधायकों के टिकट कटने की खबर फिलहाल सूत्रों और राजनीतिक चचाओं पर आधारित है। अंतिम फैसला BJP का

केंद्रीय एवं राज्य नेतृत्व करेगा।

केशव मौर्य ने भी दिए बदलाव के संकेत

सीटिंग विधायकों के टिकट कटने की चचाओं पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे सार्वजनिक नहीं होते। उन्होंने संकेत दिया कि प्रत्येक चुनाव में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को अवसर दिया जाता है। मौर्य के मुताबिक 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कोई एक व्यक्ति या केवल प्रदेश संगठन नहीं करता। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने 2017 जैसी बड़ी जीत हासिल करने के लिए जरूरी संगठनात्मक फैसले लेने की बात कही। 2024 लोकसभा चुनाव से लिया सबक BJP की मौजूदा रणनीति के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव का अनुभव भी अहम माना जा रहा है। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को कई सीटों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी का सामना करना पड़ा था।

कई क्षेत्रों में मतदाताओं की शिकायत रही कि वे केंद्र और राज्य सरकार के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन स्थानीय सांसदों की सक्रियता अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। इखढ अब विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति दोहराने से बचने के लिए विधायकों की जमीनी स्थिति पर विशेष ध्यान दे रही है।

SP-कांग्रेस गठबंधन और PDA पर भी निशाना

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संभावित समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दल पहले भी गठबंधन कर चुके हैं और उसके परिणाम सामने आ चुके हैं।

अखिलेश यादव के ढऊअ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर भी मौर्य ने सवाल उठाए। उन्होंने इसे असफल राजनीतिक फॉर्मूला बताते हुए सपा पर पिछड़ों और दलितों के हितों के लिए पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाया।

2027 से पहले संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी?

उत्तर प्रदेश में इखढ के सामने 2027 में सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। ऐसे में पार्टी मौजूदा विधायकों की लोकप्रियता, क्षेत्रीय सक्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता का आकलन कर रही है। करीब 200 सीटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चा ने जरूर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, लेकिन अंतिम तस्वीर पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल इखढ की रणनीति का केंद्र स्थानीय नाराजगी कम करना, एंटी-इनकंबेंसी पर लगाम लगाना और चुनावी मैदान में नए चेहरों के जरिए सत्ता की हैट्रिक का रास्ता मजबूत करना बताया जा रहा है।

फडणवीस को सुपर पावर! अब मंत्रियों के फैसले पलट सकेंगे CM

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

मुंबई, 19 अगस्त 2026। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कामकाज के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री के अधिकारों को और स्पष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के कामकाज के नियम, 2026 के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जनहित में किसी भी मंत्री के फैसले की समीक्षा कर उसे बदलने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, ऐसे निर्णय के कारण मुख्यमंत्री को लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

मुख्यमंत्री के अधिकार हुए स्पष्ट

नए नियमों के अनुसार विभागीय कामकाज की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित मंत्री की ही रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री को किसी मंत्री द्वारा लिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने और आवश्यकता पड़ने पर उसे संशोधित करने का स्पष्ट अधिकार होगा।

इस प्रावधान का इस्तेमाल मुख्यमंत्री तब कर सकेंगे, जब उन्हें लगे कि संबंधित फैसला व्यापक जनहित में पुनर्विचार योग्य है। फैसले में बदलाव के पीछे के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा। राजनीतिक तौर पर अहम बदलाव सरकार की ओर से यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया को स्पष्ट करने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। नए नियमों से मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्रियों के बीच अधिकारों की सीमा पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो गई है।

इस व्यवस्था के तहत बड़े या संवेदनशील विभागीय फैसलों पर मुख्यमंत्री की भूमिका अधिक प्रभावी हो सकती है।

2023 के हाई कोर्ट फैसले से जुड़ा है मामला मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर यह बदलाव 2023 के एक महत्वपूर्ण मामले की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़े मामले में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के फैसले पर रोक लगाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मुख्यमंत्री के आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि उस समय लागू कामकाज के नियमों के तहत मुख्यमंत्री को संबंधित मंत्री के स्वतंत्र निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं था।

नए नियमों में हस्तक्षेप का प्रावधान

महाराष्ट्र सरकार के 2026 के नए कामकाज नियमों में मुख्यमंत्री की इस भूमिका को स्पष्ट रूप से नियमों का हिस्सा बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े नियम पहले से लागू रहे हैं, लेकिन नए प्रावधान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करते हैं। इस बदलाव के बाद महाराष्ट्र की सत्ता व्यवस्था में मुख्यमंत्री की भूमिका और मजबूत मानी जा रही है। हालांकि, मुख्यमंत्री को इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय जनहित का आधार और अपने निर्णय के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

BJP का बड़ा दांव, यूपी में मुस्लिम वोटों पर नजर

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

लखनऊ, 19 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (इखढ) ने अपने संगठन में दो प्रमुख मुस्लिम चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का संकेत दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं का संबंध उत्तर प्रदेश से है और पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनकी सक्रियता रही है। ऐसे में इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद बढ़ाने की इखढ की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी पर खास नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था। इखढ अब इसी सामाजिक आधार में अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है।

कुंवर बासित अली को जमीनी स्तर पर सक्रिय मुस्लिम नेता के रूप में देखा जाता है, जबकि तारिक मंसूर का जुड़ाव शिक्षा और बौद्धिक वर्ग से रहा है। इखढ को उम्मीद है कि दोनों नेताओं की अलग-अलग सामाजिक एवं क्षेत्रीय पकड़ पार्टी को मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाने में मदद करेगी।

बासित अली को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कुंवर बासित अली ने इखढ में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया और संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान मिलने के बाद उनके सामने मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी का संवाद मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी। उनके नेतृत्व में पहले भी सदस्यता अभियान, चौपाल और संवाद कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं। इखढ की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचाने और पार्टी के प्रति राजनीतिक संवाद बढ़ाने की रही है।

तारिक मंसूर का अनुभव बनेगा ताकत

प्रोफेसर तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उनके अनुभव को इखढ संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी में उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तारिक मंसूर और बासित अली की पृष्ठभूमि अलग-अलग होने के बावजूद इखढ को उम्मीद है कि दोनों नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की पहुंच को व्यापक बनाने में भूमिका निभा सकते हैं।

PDA और ट समीकरण की काट की कोशिश

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी ढऊअ समीकरण प्रमुख राजनीतिक रणनीति रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम-यादव यानी ट समीकरण भी सपा के पारंपरिक सामाजिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

BJP की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चे को सक्रिय करने और मुस्लिम नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने को इसी राजनीतिक समीकरण के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का प्रयास मुस्लिम समुदाय के बीच सीधे संवाद के जरिए अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का है।

पसमांदा मुस्लिमों पर भी फोकस

BJP पिछले कुछ वर्षों से पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर देती रही है। पार्टी की रणनीति में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्गों के बीच केंद्र तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना भी शामिल रहा है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग मुस्लिम सामाजिक समूहों के बीच प्रभाव बनाने की कोशिश इखढ की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकती है।

असली परीक्षा 2027 के चुनाव में

BJP की नई रणनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के मजबूत सामाजिक समीकरण को चुनौती देना है। पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर नए प्रयोग कर रही है।

हालांकि, केवल संगठन में मुस्लिम चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से चुनावी लाभ कितना मिलेगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली की नई जिम्मेदारियों के बाद अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी और मुस्लिम समुदाय के बीच संवाद को कितना प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में इखढ की यह रणनीति मुस्लिम मतदाताओं के बीच कितना असर पैदा करती है और क्या समाजवादी पार्टी के मजबूत सामाजिक आधार में सेंध लगाने में सफल होती है, इसका फैसला अंततः चुनावी परिणाम ही करेंगे।

अंकिता हत्याकांड में फिर झटका, सभी आरोपियों की जमानत खारिज

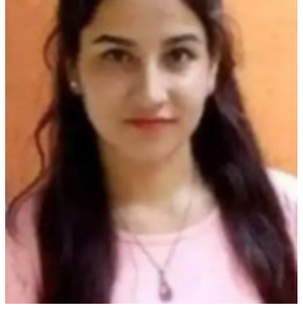

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

देहरादून, 19 अगस्त 2026। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। सरकार की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी किए जाने के बाद आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी।

प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अंकिता को न्याय दिलाने और दोषियों को कानून के तहत कठोर सजा सुनिश्चित करने के लिए शुरू से ही गंभीर रही है।

त्वरित कार्रवाई से शुरू हुई थी जांच

घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई।

जांच के दौरान करीब 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें लगभग 100 गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।

बार-बार खारिज हुई जमानत

सरकार के अनुसार, मजबूत जांच और अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते आरोपियों की जमानत अर्जियां कई बार खारिज हुईं और वे मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान जेल में रहे। बाद में मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

सरकार का कहना है कि ताजा जमानत याचिकाओं के खारिज होने से अभियोजन की ओर से पेश किए गए मामले को न्यायिक स्तर पर मिली मजबूती भी सामने आती है।

परिवार की मांगों को दी प्राथमिकता

प्रदेश सरकार ने दावा किया कि पूरे मामले में अंकिता के माता-पिता और परिवार की भावनाओं को प्राथमिकता दी गई। परिजनों की मांग के अनुरूप सरकारी अधिवक्ताओं में बदलाव किया गया।

परिवार की ओर से उच्चकजांच की मांग किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मांग का सम्मान करते हुए मामले की उच्चकजांच के आदेश भी दिए थे।

परिवार को आर्थिक मदद और रोजगार

सरकार के मुताबिक अंकिता के परिवार को ?25 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की दिशा में भी कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की शुरूआत से ही यह स्पष्ट किया था कि अपराध कितना भी गंभीर हो और आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए गिरफ्तारी, रक्ळ जांच, चार्जशीट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, मजबूत अभियोजन और परिवार की मांगों के अनुरूप उठाए गए कदम इसी नीति का हिस्सा रहे हैं। ताजा जमानत याचिकाओं के खारिज होने के बाद सरकार ने इसे न्याय की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि, मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं पर अंतिम स्थिति न्यायालय के आदेशों और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही तय होगी।

नरेला में रॉकेट लॉन्चर नष्ट, मणिपुर से जुड़ा आतंकी कनेक्शन

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। मणिपुर में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए गए संदिग्ध रॉकेट लॉन्चर और अन्य खतरनाक हथियारों को दिल्ली के नरेला इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने नियंत्रित अभियान के तहत नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमें शामिल रहीं।

सूत्रों के अनुसार, मणिपुर में दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से रॉकेट लॉन्चर सहित हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। जांच और सुरक्षित निपटान के लिए हथियारों को दिल्ली लाया गया था।

सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई

सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित खतरे को देखते हुए विस्फोटक सामग्री के निपटान के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। दिल्ली के नरेला के टिकरी इलाके में संयुक्त टीम ने खुले मैदान में नियंत्रित तरीके से खतरनाक हथियारों को डिस्पोज किया।

कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए विशेष सावधानी बरती गई।

हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान संदिग्धों के कब्जे से रॉकेट लॉन्चर के अलावा राइफलें, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी।

सुरक्षा एजेंसियां बरामद हथियारों के स्रोत और इनके संभावित इस्तेमाल को लेकर जांच कर रही हैं।

शहजाद भट्टी नेटवर्क पर कार्रवाई के बीच अभियान

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब सुरक्षा एजेंसियों ने कथित आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ देशभर में व्यापक अभियान चलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, 14 राज्यों में समन्वित कार्रवाई के दौरान 200 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए गए।

रिपोर्टों के मुताबिक इस कार्रवाई में आईईडी, पाकिस्तानी निर्मित होने के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी उपकरण भी बरामद किए गए थे।

ऊखइ केस में जैन की दलील—टेक्निकल जानकारी नहीं थी, अफसरों पर भरोसा किया

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। दिल्ली जल बोर्ड (ऊखइ) के कथित घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद अपनी दलीलें रखीं। जैन ने अदालत के समक्ष कहा कि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी और विभागीय तकनीकी मामलों में उन्हें अधिकारियों की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता था।

मामले में जैन समेत छह आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जैन ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की आवश्यकता और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अपने पक्ष को अदालत के सामने रखा।

STP का उद्देश्य यमुना को प्रदूषण से बचाना

जैन ने अदालत में कहा कि रळढ का उद्देश्य बिना उपचार किए गंदे पानी को यमुना में जाने से रोकना और नदी को साफ रखने

में मदद करना है। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल रही थी।

उन्होंने बताया कि नए रळढ के निर्माण में काफी समय लगने को देखते हुए मौजूदा संयंत्रों की क्षमता करीब 50 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी

जैन के मुताबिक, शुरूआती योजना में करीब ?1,546 करोड़ की लागत से 300 टऋक्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए करीब ?5 करोड़ प्रति टऋकी दर से चार पैकेज में टेंडर जारी किए गए थे। उन्होंने अदालत में कहा कि उनके पास आठ मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, लेकिन तकनीकी विषयों की विशेषज्ञता नहीं थी। इसलिए ऐसे मामलों में उन्हें संबंधित अधिकारियों पर भरोसा करना पड़ता था। जैन ने दावा किया कि संबंधित फाइल उनके पास कभी नहीं आई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 7 अगस्त को उनसे तकनीकी विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिनकी जानकारी उनके पास नहीं थी और उन्हें मामले में आरोपी नंबर एक बनाने का प्रयास किया गया।

मुझे हटाने के महीनों बाद हुआ टेंडर

सत्येंद्र जैन ने अपने बचाव में कहा कि उन्हें 30 मई 2022 को मंत्री पद से हटा दिया गया था और इसके बाद उनके पास कोई संबंधित फाइल नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि उनके विभाग छोड़ने के करीब छह-सात महीने बाद दिसंबर में टेंडर हुआ।

जैन ने सवाल उठाया कि जब उनके पास फाइल ही नहीं आई और उनके पद से हटने के महीनों बाद टेंडर हुआ, तो उन्हें इस मामले में दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। उन्होंने 1,546 करोड़ के प्रस्ताव और बाद में हुए करीब 1,938 करोड़ के टेंडर को लेकर भी सवाल उठाए।

छह आरोपी अदालत में पेश

दिल्ली जल बोर्ड मामले में एंटी-करप्शन ब्रांच (अउइ) ने मंगलवार को सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपियों में ऊखइ के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, अठ एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं।

हिरासत पर फैसला सुरक्षित

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में अउइ की हिरासत संबंधी मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जांच एजेंसी ने अंकित श्रीवास्तव की दो दिन की पुलिस रिमांड और सत्येंद्र जैन समेत अन्य आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है।

अदालत ने संकेत दिया कि पहले अंकित श्रीवास्तव की पुलिस हिरासत और उसके बाद अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत के संबंध में आदेश सुनाया जाएगा। मामले में आरोपों और बचाव पक्ष की दलीलों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

शिक्षा क्षेत्र में नागेश की मजबूत विरासत: विजयेंद्र

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

बेंगलुरु, 19 अगस्त 2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने विधानसभा में पूर्व मंत्री बी.सी. नागेश के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें सरल, मिलनसार और सज्जन व्यक्तित्व का धनी नेता बताया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बीच नागेश ने शिक्षा क्षेत्र में मजबूत नींव रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

विजयेंद्र ने कहा कि आज की राजनीति में चुनाव जीतने और शीर्ष स्तर तक पहुंचने के लिए जातीय समीकरण और धनबल को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बी.सी. नागेश ने अपनी अलग पहचान मेहनत, संगठनात्मक क्षमता और जनसेवा के माध्यम से बनाई।

उन्होंने बताया कि नागेश टिपटूर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे। बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दिया।

शिक्षा में कौशल और रचनात्मकता पर जोर

विजयेंद्र ने कहा कि नागेश का दृष्टिकोण केवल विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान देने तक सीमित नहीं था। वे बच्चों में कौशल, रचनात्मकता और व्यावहारिक क्षमता विकसित करने पर भी जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी।

उन्होंने कहा कि नागेश ने छात्र परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फरर) से जुड़े रहकर संगठनात्मक अनुभव हासिल किया और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरूआत की। अपनी सरल कार्यशैली और सहज व्यवहार के कारण उन्होंने विभिन्न वर्गों के नेताओं और कार्यकताओं के साथ बेहतर संबंध बनाए।

विजयेंद्र ने कहा कि नागेश ऐसे नेता थे, जिन्होंने बिना अनावश्यक विवादों में पड़े सभी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। कोविड महामारी के बाद शिक्षा क्षेत्र के सामने आई चुनौतियों के कठिन दौर में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत आधार देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बी.सी. नागेश का योगदान और उनका सरल व्यक्तित्व लंबे समय तक याद किया जाएगा।

गुरु-भक्ति से ही जागता है आत्मतेज: मुनि श्री वीरसागर

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

बेंगलुरु, 19 अगस्त 2026 निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीरसागर जी महाराज ने बुधवार को आचार्य श्री महान–जाने कैसे बनेह्व विषय पर प्रेरणादायी प्रवचन देते हुए कहा कि वास्तविक महानता धन, पद, प्रतिष्ठा और सांसारिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, संयम, समर्पण और निरंतर आत्मपुरुषार्थ से प्रकट होती है। मुनि श्री ने कहा कि मनुष्य सामान्यतः धन-संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद और सुख-सुविधाओं को जीवन की सफलता मान लेता है, लेकिन ये सभी उपलब्धियां परिवर्तनशील हैं। सांसारिक इच्छाएं पूरी होने के बाद भी समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत आत्मकल्याण, आध्यात्मिक साधना और मोक्ष की दिशा में किया गया पुरुषार्थ शाश्वत फल प्रदान करता है। इस मार्ग में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पूजा तक सीमित नहीं गुरु-भक्ति

आचार्य समन्तभद्र स्वामी की स्तुति विद्या का संदर्भ देते हुए मुनि श्री ने कहा कि गुरु-भक्ति केवल पूजा, वंदना या बाहरी प्रदर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

शिष्य का मन गुरु के गुणों एवं उपदेशों में रमे, दृष्टि उनके आदर्शों को देखे, कान धर्मोपदेश सुनें तथा शरीर और वाणी सेवा, विनय एवं आराधना में समर्पित रहें–यही गुरु-भक्ति का वास्तविक स्वरूप है।

उन्होंने कहा कि जब गुरु के प्रति भक्ति साधक के जीवन का निरंतर भाव बन जाती है, तब सांसारिक आकर्षण कमजोर होने लगते हैं और आत्मा में आध्यात्मिक तेज का जागरण होने लगता है।

आचार्य विद्यासागर जी के जीवन से मिली प्रेरणा

मुनि श्री ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के पीछे गुरु आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और कठोर साधना का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

उन्होंने समझाया कि दीक्षा के समय गुरु शिष्य को आध्यात्मिक संस्कार और साधना का बीज प्रदान करते हैं। गुरु अपनी ओर से ज्ञान और मार्गदर्शन देने में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन उस बीज को विकसित करने का दायित्व शिष्य का होता है। श्रद्धा, संयम, स्वाध्याय और आत्मशुद्धि के निरंतर पुरुषार्थ से ही साधक आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करता है।

गुरु ज्ञान नहीं छिपाता

मुनि श्री ने कहा कि सच्चा गुरु कभी अपने ज्ञान को शिष्य से छिपाता नहीं, बल्कि उसकी इच्छा होती है कि शिष्य भी उसी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचे। गुरु की निःस्वार्थ भावना के साथ सार्वभौमिक करुणा और समता का भाव जुड़ा होता है।

उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक पहचान प्रत्येक जीव के प्रति करुणा और मैत्री भाव रखना है। मनुष्य से लेकर सूक्ष्मतम जीव तक सभी प्राणियों के प्रति संवेदना ही धर्म की सार्थकता है। मुनि श्री ने श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि ह्लसुखी रहे सब जीव जगत केह्व केवल उच्चारण करने वाला वाक्य नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतरने वाला संकल्प बनना चाहिए। गुरु-भक्ति, आत्मसंयम और निरंतर पुरुषार्थ के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन को वास्तविक महानता की दिशा में ले जा सकता है।

PNG कनेक्शन पर सरकार की सौगात, 1 सितंबर से मिलेगी सस्ती गैस

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। देश में

LPG सिलेंडर के विकल्प के रूप में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 सितंबर 2026 से पात्र सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को लक्ष्य से अधिक नए घरेलू PNG कनेक्शन देने पर प्रत्येक कनेक्शन के लिए अतिरिक्त 200 रुट सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का उद्देश्य नए PNG कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पहले से लगाए गए लेकिन निष्क्रिय कनेक्शनों को भी दोबारा सक्रिय कराना है।

दो चरणों में लागू होगी योजना

नई व्यवस्था के तहत पात्र CGD कंपनियों को उनके निर्धारित लक्ष्य से अधिक नए और बिल वाले घरेलू ढठऋ कनेक्शन देने पर प्रति कनेक्शन 200 मानक घन मीटर (SCM) अतिरिक्त घरेलू गैस आवंटित की जाएगी। यह अतिरिक्त गैस घरेलू स्तर पर उत्पादित अपेक्षाकृत सस्ती गैस होगी। यह योजना 1 सितंबर से लागू होगी और दो चरणों में संचालित की जाएगी। प्रत्येक चरण छह महीने का होगा। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त सस्ती गैस मिलने से उऋकंपनियों को महंगी छठऋ की खरीद पर निर्भरता कुछ कम करने में मदद मिलेगी। इससे गैस खरीद की लागत घटेगी और घरेलू PNG नेटवर्क के विस्तार में कंपनियों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश की लागत वसूली में बड़ा फायदा सरकार के अनुमान के मुताबिक योजना से घरेलू ढठऋकनेक्शन के लिए किए गए निवेश की लागत वसूलने की अवधि करीब 10 वर्ष से घटकर लगभग 3 वर्ष रह सकती है। इससे कंपनियों को नए क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार और अधिक घरों तक ढठऋ पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

1.74 करोड़ घरों तक पहुंची PNG

देश में वर्तमान में करीब 1.74 करोड़ घरेलू ढठऋकनेक्शन हैं। सरकार ढठऋको छठऋसिलेंडर की तुलना में सुविधाजनक और अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ावा दे रही है।

PNG की प्रमुख सुविधा यह है कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर की तरह बार-बार बुकिंग और डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। पाइपलाइन के माध्यम से घर तक लगातार गैस पहुंचती है और उपभोक्ता मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिल का भुगतान करता है।

LPG के विकल्प के रूप में PNG पर जोर

पश्चिम एशिया संकट के दौरान LPG आपूर्ति को लेकर सामने आई चुनौतियों के बाद सरकार ने ढठऋनेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 से अब तक 5 लाख से अधिक PNG कनेक्शन गैसीफाई किए जा चुके हैं, जबकि 5.7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।

सरकार PNG अपनाने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही PNG Drive 2.0 के तहत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और LPG का इस्तेमाल करने वाली हाउसिंग सोसायटियों को PNG नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। नई योजना से सरकार को उम्मीद है कि घरेलू PNG कनेक्शनों का विस्तार तेजी से होगा और अधिक परिवारों को पाइपलाइन के जरिए नियमित गैस आपूर्ति का विकल्प मिल सकेगा।

ट्रेन में पानी-नाश्ता खरीदने से पहले सावधान, 8,349 बोतलें जब्त

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बिना अनुमति पानी, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान बेचने वालों के खिलाफ कऋळळउ ने देशव्यापी जांच अभियान तेज कर दिया है। अभियान के दौरान अब तक 8,349 स्थानीय पानी की बोतलें जब्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा बिना अनुमति बिक रही आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड ड्रिंक्स भी कार्रवाई की जद में आए हैं।

क्विक रिस्पॉन्स टीमों ने की अचानक जांच

ट्रेनों और स्टेशनों पर अनधिकृत खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए कऋळळउ ने क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT) गठित की हैं। ये टीमें अचानक ट्रेनों, प्लेटफॉर्म और खानपान से जुड़े प्रतिष्ठानों की जांच कर रही हैं।

उत्तर भारत में लखनऊ, अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, कटरा और जम्मू समेत कई स्टेशनों पर हुई जांच के दौरान हजारों स्थानीय पानी की बोतलें जब्त की गईं। वहीं अंबाला और सहारनपुर में जांच के दौरान बिना अनुमति बिक रही आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड ड्रिंक्स के 13 कार्टन भी पकड़े गए।

देशभर में निगरानी, साबरमती में भी कार्रवाई

IRCTC का अभियान केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। हावड़ा, गुवाहाटी, कामाख्या, अगरतला, कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है।

साबरमती स्टेशन पर भी ट्रेन में चढ़ाई जा रही बिना अनुमति वाली पानी की बोतलों और छाछ को मौके पर ही जब्त किया गया।

पानी से लेकर वेंडर की कऊतक जांच

IRCTC की टीमें ट्रेनों और स्टेशन कैंटीनों में कई स्तरों पर जांच कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से–

- बिना मंजूरी वाला सामानः रेल नीर के अलावा अनधिकृत या स्थानीय ब्रांड का पानी और खाद्य पदार्थ।
- ओवरचार्जिंगः निर्धारित कीमत से अधिक रकम वसूलने वाले वेंडर।
- सफाई और स्वच्छताः पेंट्री कार और खाद्य विक्रेताओं की हाइजीन व्यवस्था।
- वेंडर की पहचानः सामान बेचने वाले कर्मचारियों के पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज।

नियम तोड़ा तो जुमार्ना, लाइसेंस भी रद्द

IRCTC ने ठेकेदारों और कैटरिंग संचालकों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। अनधिकृत सामान बेचने या यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वाले वेंडरों के खिलाफ जुमार्ने की कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर या बार-बार नियम उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है। यात्रियों के लिए जरूरी सावधानी यात्रियों को सलाह दी गई है कि ट्रेन में पानी खरीदते समय अधिकृत ब्रांड और निर्धारित दर की जांच करें। संभव हो तो रेल नीर जैसे अधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को ही प्राथमिकता दें।

खाने-पीने की कोई भी वस्तु खरीदने पर बिल जरूर मांगें। बिना वर्दी या पहचान पत्र वाले अनधिकृत वेंडरों से सामान खरीदने से बचें। किसी वेंडर द्वारा अधिक कीमत वसूलने या संदिग्ध खाद्य सामग्री बेचने की स्थिति में रेलवे की अधिकृत शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करना बेहतर होगा।

नागेंद्र के इस्तीफे पर अड़े नारायणस्वामी, बोले—पूरे कर्नाटक में होगा आंदोलन

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

बेंगलुरु, 19 अगस्त 2026 विधायक परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी ने मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नागेंद्र मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन करेगी।

नारायणस्वामी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि वाल्मीकि निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नागेंद्र को पिछली सिद्धारमैया सरकार के दौरान मंत्रिमंडल से हटाया गया था। इसके बावजूद वर्तमान डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में उन्हें फिर से शामिल किए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस ने अब तक पूरी चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ऐसे में नागेंद्र को मंत्री पद पर बनाए रखना उचित नहीं है। नारायणस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग स्पष्ट है कि नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाया जाए।

चर्चा से क्या हासिल होगा?

नारायणस्वामी ने सरकार के उस रुख पर भी सवाल उठाया, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जब पहले ही कथित अनियमितताओं के आधार पर मंत्री को पद से हटाया जा चुका था, तो अब केवल चर्चा करने से क्या बदलेगा। उन्होंने कथित धनराशि को लेकर सामने आए अलग-अलग आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि मामले में वास्तविक नुकसान और वसूली को लेकर भी सरकार को स्पष्ट स्थिति बतानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी मामले में धन की कुछ राशि वापस मिल जाती है, तो क्या इससे कथित अपराध समाप्त हो जाता है?

दलित होने के नाम पर बचाव नहीं

नागेंद्र के उस बयान पर भी नारायणस्वामी ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि समुदाय से होने के कारण खुद को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी। नारायणस्वामी ने कहा कि किसी भी वित्तीय अनियमितता के मामले को जातिगत चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी समुदाय के कल्याण के लिए निर्धारित धन के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, तो केवल समुदाय का सदस्य होने के आधार पर आरोपों से बचाव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कथित धन की हेराफेरी से सबसे अधिक नुकसान उसी समुदाय के हितों को होता है, जिसके लिए राशि निर्धारित की गई थी। कांग्रेस पर भी लगाए गंभीर आरोप

विपक्ष के नेता ने कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नागेंद्र को बचाने का प्रयास कर रही है और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी।

नारायणस्वामी ने कहा कि मामला केवल किसी एक व्यक्ति के मंत्री पद पर बने रहने का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक धन की जवाबदेही और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का है। उन्होंने दोहराया कि नागेंद्र को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष राज्यव्यापी संघर्ष करेगा।

केजरीवाल पर मालीवाल का वार, बोलीं-मंत्रालय नहीं लिया, फिर भी

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) टेंडर मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए केजरीवाल पर मालीवाल का वार, बोलीं-मंत्रालय नहीं लिया, फिर भीह्व

मामले को झूठा बताया है। इसके बाद इखढ सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मालीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में लंबे समय तक आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामलों में मंत्रियों के माध्यम से काम कराया जाता था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं मंत्रालय नहीं संभालते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के पकड़े जाने पर पूरी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाती थी।

सत्येंद्र जैन कलेक्शन एजेंट

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कथित भ्रष्टाचार का दौर खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में अपनी गतिविधियां बढ़ा दीं। उन्होंने सत्येंद्र जैन को पंजाब में पार्टी का कलेक्शन एजेंट बताते हुए दावा किया कि वे बिल्डरों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों से कथित तौर पर धन जुटाते हैं।

मालीवाल ने चंडीगढ़ के सेक्टर-39 स्थित बंगले का भी उल्लेख किया और सवाल उठाया कि पूर्व मंत्री होने के बावजूद सत्येंद्र जैन वहां कथित रूप से आलीशान बंगले में कैसे रह रहे हैं। हालांकि, उनके इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया इस बयान में सामने नहीं आई है।

DJB टेंडर मामले में क्या है आरोप?

यह मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के उन्नयन और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए टेंडर से जुड़ा है। जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार टेंडर की तकनीकी शर्तों में कथित रूप से इस तरह बदलाव किया गया कि एक विशेष कंपनी को फायदा मिल सके।

आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत पायलट स्टडी कराए बिना ऐसी शर्तें जोड़ी गईं, जिससे अन्य कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई और सरकारी खजाने को कथित रूप से वित्तीय नुकसान पहुंचा।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच

जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलने का भी दावा किया गया है। निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत तथा ई-मेल के विश्लेषण से कथित तौर पर यह संकेत मिला कि टेंडर दस्तावेजों और उनसे जुड़े संशोधनों की जानकारी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही साझा की गई थी।

आरोपों की होगी जांच

मालीवाल के आरोपों के बीच ऊखइ टेंडर मामले की जांच एजेंसी द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी के बाद मामले में सामने आए आरोपों और साक्ष्यों की न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होगी। किसी भी आरोपी की दोषसिद्धि अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही तय होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यशैली पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at "Maruthi"Plaza"", No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, Advertisement 88676 89130 , RNI No. KNHIN/2026/A5540. E-Mail: news@bhaarataarth.com, Website: bhaarataarth.com, Established: 2026